साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 11, अंक : 4 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 27 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

दुनिया में हर चौथा व्यक्ति अब भी साफ पानी से वंचित- रिपोर्ट

नई दिल्ली। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10.6 करोड़ लोग सीधे नदियों, तालाबों या झीलों से पानी पीने को मजबूर हैं।

1.7 अरब लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाएं भी नहीं हैं। इनमें से 61.1 करोड़ लोगों के पास तो हाथ धोने या स्वच्छता के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। 1.7 अरब लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाएं भी नहीं हैं। इनमें से 61.1 करोड़ लोगों के पास तो हाथ धोने या स्वच्छता के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। पूरी दुनिया में अरबों लोग आज भी स्वच्छ व सुरक्षित पीने के पानी और बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं से वंचित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ ने विश्व जल सप्ताह 2025 के मौके पर अपनी नई रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑन हाउसहोल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 2000-2024= स्पेशल फोकस ऑन इनइक्वैलिटीज जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि पिछले दस सालों में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन असमानताएं अब भी गहरी हैं और सबसे कमजोर समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर चौथा व्यक्ति यानी करीब 2.1 अरब लोग सुरक्षित पीने के पानी से वंचित हैं। इनमें से 10.6 करोड़ लोग सीधे नदियों, तालाबों या झीलों से पानी पीने को मजबूर हैं। 1.7 अरब लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाएं भी नहीं हैं। इनमें से 61.1 करोड़ लोगों के पास तो हाथ धोने या स्वच्छता के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। केवल पानी ही नहीं, बल्कि 3.4 अरब लोग सुरक्षित शौचालय से भी वंचित हैं। इनमें से करीब 35.4 करोड़ लोग अब भी खुले में शौच करते हैं। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि सामाजिक गरिमा और सुरक्षा के लिए भी गंभीर समस्या है। इतना ही नहीं, 1.7 अरब लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाएं भी नहीं हैं। इनमें से 61.1 करोड़ लोगों के पास तो हाथ धोने या स्वच्छता के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। 1.7 अरब लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाएं भी नहीं हैं। इनमें से 61.1 करोड़ लोगों के पास तो हाथ धोने या स्वच्छता के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। यह समस्या हर जगह समान नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि कम विकसित देशों में रहने वाले लोग बाकी देशों की तुलना में दो गुना ज्यादा बुनियादी पानी और शौचालय सेवाओं से वंचित हैं। इन्हें मूलभूत स्वच्छता सेवाओं की तीन गुना ज्यादा कमी झेलनी पड़ती है। नाजुक हालात वाले क्षेत्रों में सुरक्षित पानी की पहुंच बाकी देशों से 38 प्रतिशत अंक कम है। यानी गरीबी, असुरक्षा और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा कठिनाई झेलते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। 2015 से 2024 के बीच ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित पानी की पहुंच 50 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गई। इसी अवधि में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा 52 फीसदी से बढ़कर 71 फीसदी हो गई। लेकिन शहरी क्षेत्रों में स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है। यानी गांवों में थोड़ी प्रगति हुई है, पर शहरों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महिलाएं और किशोरियां इस संकट का बोझ ज्यादा उठाती हैं। 70 देशों के आंकड़े दिखाते हैं कि अधिकांश महिलाओं और लड़कियों के पास माहवारी के समय बदलने के लिए जगह और सामग्री तो है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं। किशोरियां (15 से 19 वर्ष) माहवारी के दौरान अक्सर स्कूल, काम या सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पातीं। ज्यादातर देशों में महिलाएं और लड़कियां ही पानी लाने की जिम्मेदारी निभाती हैं। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में वे रोजाना 30 मिनट से ज्यादा समय पानी लाने में खर्च करती हैं। इसका सीधा असर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक यह लक्ष्य रखा है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित पानी, शौचालय और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध हों। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा गति से यह लक्ष्य पाना मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट में पहली बार भारत के लिए कुल अनुमान उपलब्ध है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता पर नए एकत्रित आंकड़े पिछली रिपोर्ट की तुलना में आंकड़ों की उपलब्धता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। भारत के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मुताबिक, फरवरी 2025 तक, स्वच्छता सुविधाओं वाले 17 फीसदी घर मल-अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से जुड़े थे। खासतौर पर खुले में शौच को खत्म करना और बुनियादी पानी व स्वच्छता सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाना अब भी संभव है, लेकिन इसके लिए सरकारों और संगठनों को बहुत तेजी से काम करना होगा। वहीं सभी लोगों तक सुरक्षित और प्रबंधित सेवाएं पहुंचाना अब असंभव के करीब दिखने लगा है। रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ के डॉ. रूडिगर क्रेच के हवाले से कहा गया है कि पानी, शौचालय और स्वच्छता कोई विलासिता नहीं बल्कि बुनियादी मानव अधिकार हैं। हमें सबसे कमजोर समुदायों तक तुरंत पहुंचना होगा। यूनिसेफ की सेसिलिया शार्प ने कहा कि जब बच्चों को सुरक्षित पानी और स्वच्छता नहीं मिलती, तो उनकी सेहत, पढ़ाई और भविष्य खतरे में पड़ जाते हैं। खासकर लड़कियां पानी लाने और माहवारी के कारण ज्यादा कठिनाई झेलती हैं। अगर रफ्तार यही रही, तो हर बच्चे तक सुरक्षित पानी और शौचालय का वादा पूरा नहीं हो पाएगा। यह रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि पानी और स्वच्छता सेवाएं केवल विकास का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन और गरिमा का मूलभूत अधिकार हैं। अरबों लोग अब भी इन सुविधाओं से वंचित हैं और अगर तुरंत और बड़े पैमाने पर कदम नहीं उठाए गए, तो 2030 तक हर व्यक्ति तक सुरक्षित पानी और शौचालय पहुंचाने का सपना अधूरा रह जाएगा।

अमृत 2.0 परियोजना के अंतर्गत भोपाल शहर के 30 हजार घरों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता होगी सुनिश्चित

भोपाल (एजेंसी)मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल देश के सुंदरतम शहरों में से एक है। प्रदेश की राजधानी के विकास को सुनियोजित करते हुए भोपाल को राज्य सरकार मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका लाभ भोपाल के आसपास के जिलों को भी मिलेगा। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों के आवागमन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वेस्टर्न बायपास भी विकसित किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 तक भोपाल में मेट्रो ट्रेन का संचालन भी आरंभ होगा। भोपाल के बड़े तालाब में कश्मीर की डल झील के समान शिकारो का संचालन भी पर्यटन विकास निगम के सहयोग से किया जाएगा। भोपाल में नगर निगम के माध्यम से प्रमुख मार्गों पर भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। साथ ही नगर में विशाल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नगरपालिका निगम भोपाल द्वारा निर्माण कार्यों के भूमिपूजन, नियुक्ति-पत्र वितरण और सफाई मित्रों के सम्मान के लिए कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में अमृत 2.0 परियोजना के अंतर्गत रुपए 582.32 करोड़ की लागत से विभिन्न जलापूर्ति संबंधी कार्यों और 16 करोड़ 76 लाख रूपए लागत से विभिन्न वार्डों में होने वाले 50 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। साथ ही नियुक्ति एवं अनुकंपा-पत्र प्रदान किए और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भोपाल को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होने पर सफाई मित्रों का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रत्येक भारतवासी के जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप ही अमृत 2.0 परियोजना में भोपाल शहर के 30 हजार घरों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी की जीवटता के परिणामस्वरूप ही देश में नगरीय विकास के साथ नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार भी तीव्र गति से हो रहा है। इससे आम आदमी का जीवन सरल और सुगम होगा। प्रदेश में 295 नगरों में विकास कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत में नगरीय व्यवस्था प्राचीनकाल से ही व्यवस्थित और समृद्ध रही है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसके उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। विश्व में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की साख है। भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र हो या राज्य, जब कोई भी योजना लागू होती है तो सबसे पहली भूमिका निकायों की होती है। भोपालवासियों ने ऐतिहासिक रूप से अपने जीवंत लोकतांत्रिक संस्कारों का परिचय दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भोपाल में आरंभ हुआ विलीनीकरण आंदोलन इसका उदाहरण है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की सक्रियता और भारतीय सेना द्वारा देशवासियों को दिए गए सुरक्षा के अहसास से हमारी अर्थव्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में विकास की गति तेज हुई है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में नगरों का विकास अति महत्वपूर्ण है। नगरों में लगातार रोजगार के अवसर सृजित होते हैं तो नगरों का आकार बढ़ता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरों के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जो मील का पत्थर साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्मार्ट सिटी विकसित करने और स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत की। इस वर्ष भोपाल को स्वच्छता में दूसरा स्थान मिला है। अमृत परियोजना 2.0 योजना से शहरों की समस्याओं को दूर करने और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए टंकियों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने भोपलवासियों से भोपाल को अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर-1 बनाने के लिए हरसंभव योगदान का आहवान किया।

महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय ने कहा कि भोपाल नगर निगम द्वारा अमृत परियोजना 2.0 योजना के अंतर्गत भविष्य की दृष्टि से पेयजल के लिए 4 फिल्टर प्लांट और 4 इंटेकवेल बनाए जाएंगे। साथ ही 36 उच्चस्तरीय टंकियों से 700 किमी लंबी पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। भोपाल नगर निगम के 31 कर्मचारियों की असमय मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के पत्र वितरित किए जा रहे हैं। सीधी भर्ती से चयनित 24 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सफाई मित्रों के सहयोग के कारण ही भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण में उपलब्धि प्राप्त हुई है। इस सफलता के लिए सफाई मित्रों का सम्मान हम सबका दायित्व है। कार्यक्रम मेंपूर्व प्रोटेम स्पीकर एवं विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, विधायक श्री भगवान दास सबनानी, श्री रवीन्द्र यति, भोपाल नगर निगम के पार्षद, अधिकारी-कर्मचारी, सफाई मित्र तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

हरित ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए मध्यप्रदेश बन रहा है आकर्षण का केन्द-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और मैनिट के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहयोग से हुआ एमओयू

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है। हरित ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए मध्यप्रदेश आकर्षण का केन्द्र बन रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यहां अपनी निर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक हैं। उद्योगों के साथ कृषकों और जनसामान्य को सौर ऊर्जा व अन्य वैकल्पिक स्त्रोतों से किफायती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने की दिशा में हो रहे शोध और नवाचारों को राज्य सरकार हरसंभव सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेक्का क्लाइमेट फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री क्ले स्ट्रेंजर और सुश्री सीमा पॉल, यूनिवर्सिटी ऑफ़ केलिफोर्निया बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर (आईईसीसी) के सीनियर एडवाइजर श्री मोहित भार्गव से मंत्रालय में हुई सौजन्य भेंट के दौरान यह बात कही। बैठक में सहयोग के उद्देश्यों पर चर्चा के साथ स्वच्छ एवं सतत् भविष्य के लिये साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहयोग से नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग और मौलाना आजाद राष्ट्रीय

प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट), भोपाल के बीच एमओयू हुआ है। इसके अंतर्गत मैनिट में गुरुवार को 'सेंटर फॉर मिशन ऑन एनर्जी ट्रांजिशन' (सीएमइटी) का शुभारंभ हुआ। यह केन्द्र भारत की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता के क्षेत्र में कार्य करेगा और अकादमिक-नीतिगत और औद्योगिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत आवश्यक सुझाव एवं रणनीतियां निर्धारित करने में सहयोग देगा। मैनिट भोपाल के निदेशक श्री के.के. शुक्ला ने कहा कि कैलेफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले एवं ग्लोबल पार्टनर sequoia Climate Fondation के सहयोग से प्रारंभ केन्द्र भारत में ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिये अकादमिक नीति निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच उत्कृष्ट सहयोग को दर्शाती है। कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी संस्थाएं जीआईज़ेड, सीईईडब्ल्यू, डब्ल्यूआरआई, सीएसआईएस और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। ऊर्जा परिवर्तन मिशन केन्द्र (ष्टरूश्वञ्ज) के प्रारंभ होने से स्वच्छ एवं नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों पर उन्नत शोध किया जा सकेगा। नीति निर्माताओं को डेटा आधारित सुझाव एवं समाधान उपलब्ध कराये जा सकेंगे। ग्रिड स्थिरता, ऊर्जा भंडारण और डिमांड साइड प्रबंधन के लिए नवाचारों का विकास किया जा सकेगा। साथ ही प्रशिक्षण कार्यशालाओं और वैश्विक ज्ञान विनिमय के माध्यम से क्षमता निर्माण करने में भी मदद मिलेगी।` मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

पिछले 11 वर्षों में 30% बढ़ी सौर ऊर्जा, विद्युत उत्पादन के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का हो रहा है उपयोग

भोपाल (एजेंसी)मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान युग में विद्युत (ऊर्जा) का महत्व वायु और जल के समान है। गर्व का विषय है कि हम उद्योगों और किसानों सहित सभी प्रदेशवासियों की बिजली की मांग के साथ देश की बिजली की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की मेट्रो ट्रेन मध्यप्रदेश की बिजली से चल रही है। अब इस तरह की योजना बनाई जा रही है कि वर्ष 2047 तक बिजली की कोई कमी नहीं होगी, प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस रहेगा। प्रदेश में विद्युत उत्पादन के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। देश में क्लीन एनर्जी के लिए गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा 30 प्रतिशत बढ़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 6 विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त 1060 कार्मिकों को नियुक्त-पत्र वितरण और अभिनंदन समारोह को रवीन्द्र भवन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को औषधीय पौधा भेंट कर स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बिजली कंपनियों के द्वारा एक हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। प्रदेश की बिजली कंपनियों में 51 हजार से अधिक नए पद भरे जाएंगे। इससे बिजली कम्पनियों की स्थिति सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों को लगभग 20 हजार 267 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस वर्ष दी जा रही है। प्रदेश के एक करोड़ से अधिक परिवारों को बिजली विभाग ने 6445 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। प्रदेश में बिजली तैयार करने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। राज्य के 32 लाख किसानों को सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में उत्पादित क्लीन एनर्जी से बिजली, उद्योग का रूप ले रही है। प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा अपनी स्वयं की बिजली बनाने की पहल लोक स्वास्थ्य विभाग ने आरंभ की है। इससे ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी बढ़ेगी तथा प्रबंधन के लिए दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर प्रदेश की विभिन्न बिजली कंपनियों की उपलब्धियों पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्युत कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट भी की। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नव नियुक्त विद्युत कार्मिकों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सभी बिजली कंपनियों के लिये 51 हजार से अधिक नियमित पद स्वीकृत करने पर ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पगड़ी पहना कर तथा अंग वस्त्रम और प्रशस्ति-पत्र भेंट कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के सम्मान में प्रशस्ति-पत्र का वाचन भी किया गया। इस अवसर पर नव नियुक्त कर्मिकों के अभिभावक भी उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली कंपनियों में बड़ी संख्या में नियुक्ति देकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बिजली कंपनियों को जीवनदान प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नियमित पद स्वीकृत किये गये हैं। इसीलिये आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग लगातार बिजली उपभोक्ताओं और किसानों के हित में कार्य कर रहा है। किसानों को अब कड़कड़ाती ठंडी रातों में सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। अब इन्हें सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने अधोसंरचना सुधार के लिये राशि की जरूरत पर भी बल दिया। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई ने कहा कि 1000 से अधिक युवा आज ऊर्जा विभाग से नियुक्ति-पत्र लेकर जाएंगे। उनका और उनके अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रदेश की 6 ऊर्जा कंपनियों में 51 हजार 700 नए स्थाई पद स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रयास प्रदेश को भारत में ऊर्जा क्षेत्र में नए मानकों के साथ स्थापित करेगा। ऊर्जा विभाग ने हमेशा प्रदेश और देश की ऊर्जा मांग को पूरा किया है। प्रदेश का ऊर्जा विभाग सौर ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि प्रदेश में आने वाले नए उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों का उनके सहयोग के लिये आभार माना। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक सर्वश्री रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री, एमडी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी श्री अविनाश लवानिया सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन-संधारण की नीति टिकाऊ, जनभागीदारी आधारित और दीर्घकालिक प्रभाव वाली हो

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता केवल हर घर तक नल से जल पहुँचाने की ही नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि पेयजल सुविधा आने वाले वर्षों तक सतत और गुणवत्तापूर्ण रूप में उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण की नीति को इस प्रकार तैयार किया जाय, जिससे हर गांव में स्वच्छ पेयजल की स्थायी व्यवस्था बने और किसी भी परिवार को पानी के लिए कठिनाई न उठानी पड़े। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजनाओं के संचालन एवं संधारण नीति के प्रारूप पर हुई बैठक में यह बात कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन योजनाओं को निर्माण कार्य तक ही सीमित न रखकर संचालन और रखरखाव की ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे आने वाले वर्षों में भी योजनाएँ पूरी क्षमता से कार्य करती रहें। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ग्रामीण अपने स्तर पर भी योजनाओं की देखरेख कर सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ किए गए जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार किये गये ग्रामीण नलजल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नीति को सक्षम स्वीकृति उपरांत 03 वर्षों के लिये लागू किया जाये। इस नीति के लागू होने से समूह जलप्रदाय योजनाओं की भांति एकल ग्राम नलजल योजनाओं का सुचारू एवं दीर्घकालिक संचालन हो सकेगा। इस नीति के अनुसार ग्रामीण नलजल योजनाओं का संचालन, संधारण एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री पी. नरहरि ने बताया कि प्रदेश में अगस्त 2019 तक जहाँ केवल 12.11 प्रतिशत अंतर्गत 13 लाख 53 हजार ग्रामीण परिवारों को ही नल से जल मिल रहा था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 78 लाख 64 हजार से अधिक हो गई है। इस प्रकार 70.41 प्रतिशत ग्रामीण परिवार नल से जल सुविधा से जुड़ चुके हैं। कुल 1 करोड़ 11 लाख 69 हजार परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन का कार्य वर्ष 2027 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। समूह नलजल की 147 इसी प्रकार कुल योजनाओं में से अब तक 52 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं जिनसे 4 हजार 285 ग्रामों में जलापूर्ति की जा रही है। शेष 95 योजनाएँ प्रगति पर हैं। प्रमुख सचिव श्री नरहरि द्वारा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित हो रही नलजल योजनाओं के दीर्घकालिक एवं प्रभावी संचालन हेतु विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श उपरांत तैयार की ग ग्रामीण नलजल योजना संचालन-संधारण एवं प्रबंधन नीति की विस्तार से जानकारी दी गई। इस नीति के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण नलजल योजना का संचालन पूर्व की भांति संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा किये जाने तथा ग्राम पंचायतों को योजना के संचालन में सहयोग देने हेतु तथा योजना संचालन की व्यवस्था को सदृढ करने के उददेश्य से योजना के संधारण से संबंधित कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से किये जाने की जानकारी दी गई।

ग्रीनलैंड की पिघलती बर्फ से समुद्री जीवन का विस्फोट, क्या संतुलन में आएगी गड़बड़ी?

ग्रीनलैंड बहुत दूर उत्तरी ध्रुव के पास, ग्रीनलैंड नाम की बर्फ से ढकी एक विशाल धरती है। यहां बर्फ इतनी मोटी और फैली हुई है कि इसे देखकर लगता है मानो पूरी धरती पर सफेद चादर बिछी हो। लेकिन अब यह चादर धीरे-धीरे पिघल रही है।

ग्रीनलैंड की यह बर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की भंडारों में से एक है। हर साल यहां की बर्फ लगभग 293 अरब टन पिघलकर समुद्र में मिल जाती है। यह इतना पानी है कि यदि इसे टैंकरों में भरना हो तो अनगिनत टैंकर लगेंगे। गर्मियों के दिनों में यह पिघलना और तेज हो जाता है। खासकर जेकबशावन ग्लेशियर से तो हर सेकंड तीन लाख गैलन पानी समुद्र में गिरता है। ग्रीनलैंड के चारों ओर 250 से अधिक ग्लेशियर हैं। हर एक ग्लेशियर पिघलकर अपने-अपने क्षेत्र के समुद्र को प्रभावित कर रहा है। अब सवाल उठता है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ पिघलकर समुद्र में जाती है, तो उसका असर क्या होता है? क्या यह केवल समुद्र का स्तर बढ़ाती है या फिर और भी कुछ होता है? कम्युनिकेशन अर्थ नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने देखा कि यह पिघला हुआ पानी बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करता है। समुद्र का पानी खारा होता है, जबकि ग्लेशियर से आने वाला पानी मीठा या ताजा होता है। मीठा पानी हल्का होता है और जब यह खारे पानी में गिरता है तो ऊपर की ओर उठने लगता है। ग्रीनलैंड के चारों ओर 250 से अधिक ग्लेशियर हैं। हर एक ग्लेशियर पिघलकर अपने-अपने क्षेत्र के समुद्र को प्रभावित कर रहा है। लेकिन यही ऊपर उठने की प्रक्रिया एक जादू कर जाती है। जैसे ही यह पानी उठता है, यह समुद्र की गहराई में छिपे पोषक तत्वों को भी ऊपर खींच लाता है। इन पोषक तत्वों में आयरन और नाइट्रेट जैसे तत्व होते हैं, जो पौधों और जीवों के लिए खाद का काम करते हैं। समुद्र की सतह पर रहते हैं बेहद छोटे-छोटे जीव जिन्हें हम फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। ये फाइटोप्लैंकटन समुद्र की पूरी भोजन श्रृंखला की नींव हैं। इन्हें छोटे जीव जैसे क्रिल खाते हैं, फिर मछलियां क्रिल खाती हैं और मछलियों को बड़ी मछलियां और व्हेल जैसे जीव खाते हैं। यानी, यदि फाइटोप्लैंकटन न हों तो समुद्र की पूरी खाने की श्रृंखला टूट जाएगी। वैज्ञानिक कई सालों से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह पिघलता पानी समुद्र में कैसे असर डालता है। लेकिन ग्रीनलैंड जैसे इलाके में शोध करना आसान नहीं है। वहां की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी जमीन और विशालकाय हिमखंड रास्ता रोक देते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का सहारा लिया। नासा और एमआईटी के वैज्ञानिकों ने एक्को-डार्विन नाम का एक सुपरकंप्यूटर मॉडल बनाया। इसमें पिछले 30 सालों के समुद्र से जुड़े आंकड़े भरे गए, जैसे पानी का तापमान, खारापन, गहराई पर दबाव आदि। जब शोधकर्ताओं ने ग्रीनलैंड के इस ग्लेशियर का मॉडल बनाया तो एक अनोखा नतीजा सामने आया। पता चला कि पिघले पानी से ऊपर लाए गए पोषक तत्वों की वजह से फाइटोप्लैंकटन की संख्या गर्मियों में 15 से 40 फीसदी तक बढ़ सकती है। यह खोज सुनकर कुछ लोग खुश हुए कि समुद्र में जीवन बढ़ रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी। ग्लेशियर का पिघलना केवल अच्छा असर नहीं डालता। एक तरफ तो यह फाइटोप्लैंकटन की वृद्धि करता है। दूसरी तरफ, यह समुद्र के पानी के तापमान और खारेपन को बदल देता है। साथ ही, समुद्र के पानी की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो रही है। लेकिन संतुलन की बात यह है कि फाइटोप्लैंकटन अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, जिससे नुकसान की भरपाई हो जाती है।

आने वाले 3 वर्ष में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार 100 लाख हेक्टेयर तक करें

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की समृद्धि के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सिंचाई क्षेत्र का निरंतर विस्तार आवश्यक है। इसके लिए जल संसाधन विभाग और सभी संबंधित एजेंसियां तेजी से कार्य करें। वर्तमान में शासकीय स्त्रोतों से प्रदेश में सिंचाई प्रतिशत 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। इसे शीघ्र ही दोगुना करने का लक्ष्य ध्यान में रखकर कार्य किया जाए जिससे आने वाले 3 वर्ष में प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हो जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि के साथ ही उद्योग क्षेत्र में पानी देने, पेयजल प्रबंध और ऊर्जा उत्पादन में जल का उपयोग जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से हो रहा है। सिंचाई के 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लक्ष्य के अनुसार जल संसाधनों के समुचित उपयोग को पूरी प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न परियोजनाओं से बढ़ रहे सिंचाई क्षेत्र की जानकारी भी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं जैसे केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, संशोधित पार्वती-काली-सिंध चंबल लिंक परियोजना को अति उपयोगी बताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के लगभग आधे जिलों की तस्वीर बदल जाएगी। राज्य के अंदर भी नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य प्रारंभ कर लाभ प्राप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नदियों को जोड़ने का स्वप्न भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल ने देखा जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी साकार कर हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए 90त्न राशि देने का लाभकारी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुसार राज्यों की ऐसी पहल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजनाओं के कार्य जैसे-जैसे क्रियान्वित होंगे, सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा, साथ ही खुशहाली भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल संसाधन विभाग की ओर से राज्य के अंदर नदी जोड़ो प्रकल्पों की संभावनाओं का सर्वेक्षण और अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार किया जाए। केन्द्र सरकार को ऐसे प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शिप्रा शुद्धिकरण, नदी एवं जल निकायों के विकास और घाट निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान बताया गया कि वर्तमान में शिप्रा पर लगभग 30 किलोमीटर लंबाई में घाट निर्माण का कार्य हो रहा है, यह सभी कार्य वर्ष 2027 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। घाटों के निर्माण से सिंहस्थ के दौरान एक दिन में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। शिप्रा नदी पर बैराज निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि रबी 2023-24 में प्रदेश में सिंचित रकबा 44.56 लाख हेक्टेयर था जो रबी 2025-26 में बढ़कर 52.06 हो गया है। इस तरह बीते डेढ़ वर्ष में प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र में 7.50 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसमें जल संसाधन विभाग द्वारा 2.39 और नर्मदा घाटी विकास विभाग 5.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने में सफलता प्राप्त की गई है। बताया गया कि प्रदेश में आगामी पांच वर्ष में 200 करोड़ से अधिक लागत की 38 सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप 17 लाख 33 हजार 791 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार होगा। इस वर्ष 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा, जो मोहनपुरा बांयीतट परियोजना जिला राजगढ़, चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जिला अशोकनगर, पंचमनगर सिंचाई परियोजना जिला दमोह एवं सागर, त्योंथर बहाव योजना जिला रीवा और घोघरी मध्यम परियोजना जिला बैतूल के माध्यम से संभव होगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008